बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 242 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 14 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में सनसनीखेज वारदात- पुलिस के जवान ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, कार से बीच सड़क शव फेंककर हुआ फरार

नई दिल्ली । पूर्वी दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर इलाके में सोमवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दिल्ली पुलिस के एक जवान ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी मनीष भाटी दिल्ली पुलिस के पूर्वी दिल्ली जिला एटीएस (एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड) में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। जानकारी के अनुसार, ईस्ट विनोद नगर, गली नंबर 2 निवासी मनीष की पत्नी की सोमवार तड़के तबीयत बिगड़ गई थी। उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया जा रहा था। अस्पताल जाते समय रास्ते में किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच गहरा विवाद हो गया।

दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 किलो से अधिक हाइड्रोपोनिक वीड जब्त, सीट और टॉयलेट में छिपाकर लाए थे आरोपी

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने तस्करी के अलग-अलग मामलों में तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इन यात्रियों से 6.37 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड (एक तरह का गांजा) जब्त किया गया, जिसे विमान के टॉयलेट, यात्रियों की सीटों के नीचे और सामान में छिपाकर रखा गया था। हाइड्रोपोनिक वीड गांजे की एक बहुत तेज असर वाली किस्म है, जिसे मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगाया जाता है। अलग-अलग आधिकारिक बयानों के अनुसार, बैंकॉक और फुकेत से आने वाले यात्रियों से जुड़ी इन तीन घटनाओं में कुल 6.37 किलोग्राम संदिग्ध प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया एक बयान के मुताबिक, पहले मामले में सोमवार को बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री को एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफाइलिंग के आधार पर ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया। बयान में कहा गया है कि यात्री के सामान में तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन कस्टम अधिकारियों ने विमान की तलाशी ली और पिछले दोनों टॉयलेट के अंदर छिपाकर रखे गए संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड के चार सीलबंद पैकेट बरामद किए, जिनका वजन 3.47 किलोग्राम था। बयान में कहा गया, पूछताछ करने पर यात्री ने टॉयलेट के अंदर पैकेट छिपाने की बात कबूल कर ली। एक अन्य मामले में, सोमवार को फुकेत से आए एक यात्री को APIS प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया। बयान के अनुसार, जब यात्री के सामान में कोई प्रतिबंधित सामान नहीं मिला, तो कस्टम अधिकारियों ने विमान की तलाशी ली और 12वीं लाइन की सीटों के नीचे संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड वाले छह सीलबंद पैकेट पाए, जिनका वजन 1.5 किलोग्राम था। बयान में कहा गया है कि बाद में यात्री ने विमान के अंदर पैकेट छिपाने की बात मान ली। तीसरे मामले में, रविवार को बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री को APIS प्रोफाइलिंग के आधार पर ग्रीन चैनल पार करने के बाद रोका गया। बयान के मुताबिक, एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान अधिकारियों को यात्री के सामान में कुछ संदिग्ध तस्वीरें दिखीं। तलाशी लेने पर लगभग 1.4 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड वाले दो वैक्यूम-सीलबंद पैकेट बरामद किए गए। तीनों यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 43(बी) के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि संदिग्ध प्रतिबंधित सामान को एक्ट की धारा 43(ए) के तहत जब्त किया गया।

पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका

नई दिल्ली । पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में केंद्र और राय सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे देश भर में पेपर लीक मामलों की समय-सीमा के भीतर जांच और तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक मानक प्रश्नावली और विशेष जांच प्रक्रिया तैयार करें। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में भ्रष्टाचार विरोधी, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्ति और काले धन कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के अलावा, पेपर लीक के अपराधियों और अपराध में कथित रूप से शामिल उनके परिवार के सदस्यों की चल और अचल संपत्तियों की जब्ती के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में, जिसमें केंद्र सरकार, सभी रायों और केंद्र शासित प्रदेशों, साथ ही भारत के विधि आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है, यह तर्क दिया गया है कि बार-बार होने वाले पेपर लीक के देशव्यापी प्रभाव होते हैं, जिससे छात्र और उनके परिवार गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। याचिका में कहा गया है, पेपर लीक का देशव्यापी असर हुआ है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों पर बुरा असर पड़ा है और कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। याचिका के अनुसार, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को रोकने, जांच करने और प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने में अधिकारियों की लगातार विफलता के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। याचिका में 3 मई, 2026 को कथित एनईईटी पेपर लीक

का जिक्र करते हुए कहा गया कि इस घटना ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया और परीक्षा संबंधी अपराधों से निपटने में प्रणालीगत कमियों को उजागर किया। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं के कारण छात्रों को वित्तीय कठिनाई, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों की हानि, गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याएं, बढ़ती आत्महत्याओं का बोझ झेलना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पारसनाथ डेवलपर्स और उसके निदेशकों के बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने का आदेश दिया। साथ ही कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए। अदालत ने वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपने घर का कब्जा पाने के लिए पिछले 20 वर्षों से किए जा रहे संघर्ष का संज्ञान लेते हुए यह सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने नियामक प्राधिकरणों की निष्क्रियता पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने हरियाणा सरकार के तंत्र और बिल्डर के बीच संभावित मिलीभगत की भी आशंका व्यक्त की। मामला कैंसर से उबर चुकीं रीता टिकू और लोकेश टिकू की ओर से दायर याचिका से संबंधित है। दोनों ने गुरुग्राम के सेक्टर-53 स्थित पारसनाथ एक्सोटिका परियोजना में अपनी जीवनभर की जमा पूंजी निवेश की थी। याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2006 में आवासीय इकाइयां आवंटित की गई थीं और वर्ष 2007 की शुरुआत में फ्लैट खरीदार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। करीब 1.78 करोड़ रुपये की पूरी कीमत चुकाने के बावजूद उन्हें वर्ष 2013 तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिला। दो दशक बीत जाने के बाद भी परियोजना अब तक अधूरी है। याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2021 में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचआरईआरए) से राहत मिली थी, जिसने बिल्डर को मुआवजा देने का आदेश दिया था। हालांकि, बिल्डर ने न तो उस आदेश को चुनौती दी और न ही उसका पालन किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आदेश के क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया निरर्थक होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि एचआरईआरए द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बावजूद उनका कभी पालन नहीं कराया गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिला कलेक्टर और स्थानीय पुलिस या तो बिल्डरों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं या फिर अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिल्डर आगे भी न्यायिक प्रक्रिया से बच न सके, पीठ ने पारसनाथ हेसा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, पारसनाथ डेवलपर्स लिमिटेड तथा उनके प्रबंध निदेशकों और निदेशकों के व्यक्तिगत बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें रायों को गायों और उनके बछड़ों को वध से बचाने के लिए लागू गोवध निषेध कानूनों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पशुओं के वध से जुड़े वर्ष 2005 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संबंधित अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं।

इस पर पीठ ने कहा, अगर किसी न्यायिक आदेश का उल्लंघन हो रहा है तो आप अवमानना याचिका दायर करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध अन्य वैधानिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

केंद्र से दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा बूस्ट, 1,647 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं को मंजूरी, सीएम रेखा गुप्ता ने जताया आभार

नई दिल्ली। दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत दिल्ली सरकार की 28 प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,647 करोड़ रुपये है। इसके अलावा पूंजीगत निवेश बढ़ाने के प्रयासों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली को 756 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी स्वीकृत की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला राजधानी के विकास को नई गति देगा और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने इसे दिल्ली के बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

इन प्रमुख परियोजनाओं को मिली मंजूरी

एसएएससीआई योजना के तहत जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उनमें दिल्ली मेट्रो से जुड़ी परियोजनाएं, एलिवेटेड बारापुला कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग स्टेशन और सड़क अवसंरचना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इनके पूरा होने से परिवहन व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है।

9 जुलाई को मिली थी मंजूरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने शुरुआत से ही इन परियोजनाओं को एसएएससीआई योजना के तहत शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार प्रयास किए। इसी का परिणाम है कि 9 जुलाई 2026 को दिल्ली सरकार की सभी 28 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई।

विकसित भारत विजन को मिलेगा बल

रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में रायों में पूंजीगत निवेश और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

बेहतर वित्तीय प्रबंधन का मिला इनाम

मुख्यमंत्री के अनुसार, अतिरिक्त 756 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि इस बात का संकेत है कि पारदर्शी कार्यप्रणाली, वित्तीय अनुशासन और विकास के प्रति प्रतिबद्ध सरकारों को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलता है।

दिल्ली लक्ष्मी योजना- सरकार देगी महिलाओं को 2500 माह

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी प्रमुख योजना महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर अब दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है।

सरकार ने न सिर्फ इस योजना के नाम में बदलाव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है, बल्कि इसके तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता को लेकर भी दिशा-निर्देश स्पष्ट कर दिए हैं।

इस महत्वाकांक्षी योजना को आगामी रक्षाबंधन (28 अगस्त) के शुभ अवसर पर लॉन्च किए जाने की पूरी संभावना है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दिल्ली की पात्र महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 2,500 की वित्तीय सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य इस राशि के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी दैनिक व बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है।

किसे मिलेगा लाभ?

सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें और मापदंड तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं-

आयु सीमा- योजना का लाभ केवल 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को ही मिलेगा।

दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य - आवेदिका का पिछले कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।

आय सीमा- योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख (ढाई लाख रुपये) या उससे कम है।

कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं- सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से यह अनिवार्य किया गया है कि आवेदन करने वाली महिला का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

रक्षाबंधन पर मिलेगा तोहफा

दिल्ली सरकार इस योजना को रक्षाबंधन के दिन लागू करने की तैयारी में है, जिसे दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़े त्योहार के उपहार के रूप में देखा जा रहा है। योजना के शुरू होने से दिल्ली की लाखों मध्यमवर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सीधा संबल मिलेगा। सरकार जल्द ही इसके आवेदन की प्रक्रिया और आधिकारिक पोर्टल की जानकारी साझा करेगी।

पवन खेड़ा का बड़ा आरोप- पीएम मोदी नेतन्याहू से प्रेरित, लोकतंत्र में नहीं यकीन

नई दिल्ली ।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वे विचारधारा के स्तर पर इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से प्रेरित हैं। एनआईए से बात करते हुए खेड़ा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और उन्होंने भारत में पेगासस निगरानी विवाद को लेकर सवाल उठाए। खेड़ा ने पूछा कि असल बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी नेतन्याहू से प्रेरित हैं। वह लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते। उनके रोल मॉडल नेतन्याहू हैं। तो, जिस व्यक्ति के रोल मॉडल, हीरो या आइकन नेतन्याहू हों, क्या आप उससे किसी बेहतर चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं? इस देश में पेगासस कौन लाया, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? पेगासस स्पाइवेयर का मामला 2021 में तब सामने आया जब आरोप लगे कि इज़राइली हस्ट रूप के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सरकारों ने पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की भी आलोचना की और कहा कि इससे भारत को कोई ठोस फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी जनता का पैसा खर्च किया गया। उन्होंने इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारतीय टॉफ़ी ब्रांड मेलोडी का पैकेट तोहफ़े में देने पर मोदी का मज़ाक भी उड़ाया। खेड़ा ने सवाल किया कि राहुल गांधी सरकारी खर्च पर सरकारी दौरे पर नहीं जाते। भारत के प्रधानमंत्री इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जब वह विदेश जाकर मेलोनी नाम की महिला को मेलोडी

टॉफ़ी बांटते हैं, तो क्या हमें इसका जश्न मनाना चाहिए? क्या टैक्स देने वालों के पैसे से उन्हें यही करना चाहिए? कांग्रेस नेता ने मोदी के विदेशी दौरों के नतीजों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका के साथ बहुत ही असंतुलित व्यापार समझौता किया है और दावा किया कि देश की विदेश नीति बाहरी ताकतों से प्रभावित है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर इज़राइल का समर्थन करने का आरोप लगाया और कहा कि मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले मोदी ने उस देश का दौरा किया था। खेड़ा ने कहा कि उनके इन सभी दौरों से हमें क्या मिला? अमेरिका के साथ एक बहुत ही पक्षपाती टैरिफ डील। क्या हमें उनसे यही मिलता है? डोनाल्ड ट्रंप हमारी विदेश नीति को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हमें उनसे यही मिलता है? एपस्टीन हमारी विदेश नीति को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी विदेश नीति तय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस गैर-कानूनी युद्ध से ठीक पहले इज़राइल जा रहे हैं और इज़राइल के साथ खड़े हैं। क्या एक देश के तौर पर हम यही चाहते हैं?

सम्पादकीय...

जीवनरेखा

जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। सड़क दुर्घटना, अचानक हृदयाघात, गंभीर बीमारी अथवा प्रसव जैसी आपातकालीन परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति और परिवार के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती हैं। ऐसे समय में चिकित्सा सहायता का हर एक मिनट अमूल्य होता है, क्योंकि समय पर उपचार ही कई बार जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करता है। इसी आवश्यकता को समझते हुए उत्तर प्रदेश में संचालित 108 ई.एम.टी.एस. (इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस) एम्बुलेंस सेवा आज करोड़ों लोगों के लिए भरोसे, सुरक्षा और जीवन रक्षा का पर्याय बन चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, त्वरित और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। 108 एम्बुलेंस सेवा इसी संवेदनशील और जनकल्याणकारी सोच का सशक्त उदाहरण है, जिसने संकट की घड़ी में लाखों परिवारों को नई उम्मीद दी है। स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक सफलता केवल आधुनिक अस्पतालों या चिकित्सकों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि आपातकाल की स्थिति में मरीज तक चिकित्सा सहायता कितनी शीघ्र पहुंचती है। विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए समय पर एम्बुलेंस की उपलब्धता किसी वरदान से कम नहीं होती। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 108 ई.एम.टी.एस. सेवा को एक ऐसी समर्पित आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है, जो चौबीसों घंटे, वर्ष के सभी 365 दिन बिना किसी भेदभाव के आमजन की सेवा में तत्पर रहती है। यह व्यवस्था पूरी तरह एकीकृत कॉल सेंटर आधारित प्रणाली पर संचालित होती है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक दुर्घटना, गंभीर बीमारी, हृदयाघात, प्रसव पीड़ा अथवा अन्य चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में केवल टोल-फ्री नंबर 108 डायल कर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकता है। सूचना प्राप्त होते ही अत्याधुनिक संचार प्रणाली के माध्यम से निकटतम एम्बुलेंस को मौके के लिए रवाना किया जाता है, जिससे मरीज तक कम से कम समय में चिकित्सा सहायता पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समय के साथ इस सेवा को और अधिक प्रभावी, तेज और उत्तरदायी बनाने के लिए इसके संचालन तंत्र में निरंतर सुधार किए हैं। सेवा के प्रारंभिक चरण में शहरी क्षेत्रों में एम्बुलेंस के 20 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन जुलाई 2019 से लागू नए संचालन मॉडल के अंतर्गत इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अधिकतम 15 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम निर्धारित किया गया। बेहतर तकनीक, आधुनिक प्रबंधन प्रणाली, प्रभावी निगरानी और प्रशासनिक दक्षता के परिणामस्वरूप जनवरी 2025 तक इस सेवा का वास्तविक औसत रिस्पॉन्स टाइम घटकर केवल 7.30 मिनट रह गया, जो निर्धारित मानक से भी कहीं अधिक बेहतर उपलब्धि है। यह सुधार इस बात का प्रमाण है कि समयबद्ध चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए एम्बुलेंस बेड़े का भी व्यापक विस्तार किया गया है। सेवा के शुरुआती वर्षों में जहां प्रदेश में 1,488 एम्बुलेंस संचालित थीं, वहीं वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 2,200 हो गई है। इसी प्रकार प्रत्येक एम्बुलेंस द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले औसत फेरों (ट्रिप्स) की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। संसाधनों में यह वृद्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे प्रदेश के अधिक से अधिक नागरिकों तक समयबद्ध चिकित्सा सहायता पहुंचाना संभव हुआ है। बढ़ती जनसंख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए यह विस्तार सरकार की दूरदर्शी कार्ययोजना को भी दर्शाता है। 108 ई.एम.टी.एस. सेवा की सबसे बड़ी सफलता उन करोड़ों लोगों की जिंदगी में दिखाई देती है जिन्हें समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सकी। अपनी स्थापना से लेकर जनवरी 2026 तक यह सेवा लगभग 3.60 करोड़ रोगियों तक पहुंचकर उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने और आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। यह संख्या केवल सेवा के व्यापक विस्तार का परिचायक नहीं, बल्कि उन करोड़ों परिवारों के विश्वास की भी कहानी है जिनके लिए यह एम्बुलेंस संकट की घड़ी में जीवन की नई आशा बनकर पहुंची। इस सेवा का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुंच रहा है। विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण, बुजुर्ग, महिलाएं, नवजात शिशु और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए यह सेवा किसी जीवनदायिनी व्यवस्था से कम नहीं है। दूरस्थ क्षेत्रों में जहां निजी चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं, वहां 108 एम्बुलेंस लोगों और अस्पतालों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। इससे न केवल समय पर उपचार सुनिश्चित हुआ है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आमजन का विश्वास भी लगातार मजबूत हुआ है। आज आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में आधुनिक तकनीक, त्वरित संचार प्रणाली और प्रशिक्षित मानव संसाधन का समन्वय स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रहा है। 108 ई.एम.टी.एस. सेवा इस समन्वित व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें तकनीक और मानवीय संवेदनशीलता साथ-साथ कार्य करते हैं। प्रत्येक कॉल केवल एक सूचना नहीं होती, बल्कि किसी जीवन को बचाने की जिम्मेदारी होती है, जिसे यह सेवा पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं जनसुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, आधुनिक एम्बुलेंस, बेहतर उपकरण, प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था आने वाले समय में इस सेवा को और अधिक सक्षम बनाएगी। लक्ष्य केवल एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक जरूरतमंद तक न्यूनतम समय में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता पहुंचाना है।

ईरान-अमेरिका संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाड़ी क्षेत्र पर प्रभाव

पश्चिम एशिया एक बार फिर गंभीर सैन्य तनाव के दौर से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच नाजुक युद्धविराम के बावजूद हालिया घटनाक्रम ने यह संकेत दिया है कि क्षेत्र में शांति अभी भी बेहद अस्थिर है। ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन की दिशा में मिसाइलों और ड्रोन से किए गए हमलों तथा इसके जवाब में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को नई अनिश्चितता में डाल दिया है।

इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हॉर्मुज जलडमरूमध्य बन गया है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट, नौसैनिक संसाधन तथा हथियार भंडारण केंद्र शामिल थे। इसके बाद दक्षिणी ईरान के होर्मोजगान प्रांत में स्थित बंदर अब्बास, केश्म द्वीप और हाजीआबाद जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर भी हमले किए गए। ईरानी मीडिया के अनुसार इन हमलों में सेना के एक अधिकारी की मृत्यु हुई। इन सैन्य कार्रवाइयों के कुछ ही समय बाद ईरान ने खाड़ी के कई देशों की दिशा में मिसाइल और ड्रोन दागे। कतर के गृह मंत्रालय ने बताया कि गिरते मलबे से तीन लोग घायल हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। कतर ने इन हमलों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कड़ी निंदा की। ओमान ने भी अपने क्षेत्र में ड्रोन हमलों के विरोध में ईरान के राजदूत को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत ने भी अपनी वायु सुरक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया। ईरान की इस सैन्य रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर उसका नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास माना जा रहा है। इससे पहले ईरान ने घोषणा की थी कि जलडमरूमध्य को «अगली सूचना तक बंद» किया जा रहा है और केवल उन्हीं जहाजों को गुजरने की अनुमति होगी जो ईरान द्वारा स्वीकृत मार्ग का उपयोग करेंगे। इससे पहले एक साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले की घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर चिंता और बढ़ा दी थी। हॉर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री मार्ग विश्व के तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार का प्रमुख प्रवेश द्वार है। युद्ध से पहले दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का परिवहन इसी मार्ग से होता था। यदि यहां आवागमन बाधित होता है, तो उसका सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बंदर अब्बास और केश्म द्वीप ईरान के लिए विशेष रणनीतिक महत्व रखते हैं। बंदर अब्बास देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहां से अधिकांश आयात और निर्यात संचालित होते हैं। दूसरी ओर केश्म द्वीप ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है, जहां नौसैनिक अड्डे, रडार प्रणाली और संचार केंद्र स्थित हैं। इन दोनों स्थानों पर नियंत्रण का अर्थ है हॉर्मुज जलडमरूमध्य की निगरानी और समुद्री गतिविधियों पर प्रभाव बनाए रखना। अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और किसी एक देश को इस पर नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार नहीं है। सेंट्रल कमांड ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सेनाएं नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरी ओर ईरान का तर्क है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री हितों की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में निगरानी और नियंत्रण आवश्यक है। इस संघर्ष का आर्थिक प्रभाव पहले ही दिखाई देने लगा है। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें कई वर्षों के उच्च स्तर तक पहुंच गई हैं। ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों, विशेषकर भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है। यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो परिवहन लागत बढ़ेगी, महंगाई में वृद्धि होगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी स्थिति जटिल बनी हुई है। हालांकि जून में अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, जिसके तहत सीमित रूप से समुद्री यातायात बहाल करने पर सहमति बनी थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी अब भी स्पष्ट दिखाई देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले यह कह चुके थे कि समझौता लगभग समाप्त हो चुका है, हालांकि बाद में उन्होंने वार्ता जारी रखने के संकेत दिए। इसके बावजूद सैन्य कार्रवाइयों का जारी रहना बताता है कि कूटनीति और संघर्ष दोनों समानांतर रूप से चल रहे हैं। ओमान इस पूरे विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। ओमानी और ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन व्यवस्था को लेकर तकनीकी और राजनीतिक वार्ताएं जारी रहेंगी। हालांकि ईरान ने अब तक निर्बाध समुद्री आवागमन की स्पष्ट गारंटी नहीं दी है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और बढ़ता है, तो इसका प्रभाव केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं रहेगा।

वैश्विक व्यापार, समुद्री बीमा, निवेश, वित्तीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति सभी प्रभावित हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी यह एक गंभीर चुनौती है कि वे दोनों पक्षों को संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के लिए प्रेरित करें। अंततः ईरान और अमेरिका के बीच यह संघर्ष केवल दो देशों का विवाद नहीं रह गया है। यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, क्षेत्रीय स्थिरता और विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर जारी टकराव यह दिखाता है कि भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किस प्रकार पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास तनाव को कम करने में सफल होते हैं या पश्चिम एशिया एक और व्यापक सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ता है।

युद्ध

हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं तो दूसरी तरफ ईरान ने भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम खत्म हो चुका है। यद्यपि ट्रम्प बार-बार यह बयान दे रहे हैं कि युद्ध विराम खत्म हो चुका है, फिर भी ईरान से बातचीत जारी रखेंगे। ईरान की आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और ईरान का कहना है कि उसे अब एकतरफा समझौता स्वीकार नहीं है। कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, जार्डन में ईरान के ताजा हमलों ने खाड़ी देशों में एक बार फिर खौफ पैदा कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने जार्डन के एयरबेस को तबाह करके रख दिया है। बहरीन और कुवैत में बिजली सप्लाई केन्द्रों पर ईरानी हमलों से वहां के शहर अंधकार में डूब चुके हैं। अमेरिका लगातार ईरान के बंदर अब्बास केश्म द्वीप, चाबहार बंदरगाह और ईरान के मिसाइल व ड्रोन रखने वाली जगहों पर बम बरसा रहा है। कुल मिलाकर युद्ध का एक नया चरण शुरू हो चुका है और यह चरण दोनों पक्षों के अहंकार और विनाश का युद्ध है। ईरान में खामेनेई के पार्थिव शरीर को ईमाम रजा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जा चुका है। अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए एक करोड़ से अधिक लोग सड़कों पर आए। अमेरिका और इजराइल को लगा था कि ईरान के लोग खामेनेई शासन से नफरत करते हैं और वे पूरी तरह से बगावत पर उतर आएंगे लेकिन अमेरिकी हमलों ने सत्ता के विरुद्ध आक्रोश कोसलत कर उसी सत्ता समर्थक क्रांति में बदल दिया। ईरान की जनता में ट्रम्प और नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश इतना बढ़ चुका है कि वे ट्रम्प की हत्या का संकल्प ले रहे हैं। इसके मायने नए संघर्ष की जमीन तैयार हो चुकी है। हेर्मुज का रास्ता व्यापार के साथ-साथ वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो सप्लाई चेन अवरुद्ध हो जाएगी, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित होगी। ईरान चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण बना रहे। अमेरिका और ईरान में हुए समझौते में तीन प्रमुख अड़चनें थीं। लेबनान से इजराइली फौजों की वापसी, ईरान की जब्त की गई सम्पत्तियों को लौटाना और होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति। ईरान ने समझौते के बाद होर्मुज तट के किनारे एक सुरक्षित मार्ग खोल दिया था। जबकि अमेरिका ओमान तट के किनारे एक वैकल्पिक मार्ग को खोलने के पक्ष में था। ईरान को डर है कि अमेरिका वैकल्पिक मार्ग को बढ़ावा देकर युद्ध के दौरान जलडमरूमध्य पर स्थापित उसके प्रभाव को छीनने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान एक इंडियानापोलिस जलमार्ग का एकमात्र संरक्षक बन उभरे। इन परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण टकराव होते हैं जिससे समझौता ज्ञापन और कमजोर हो जाता है। इंडियानापोलिस हार को भांपते हुए ट्रम्प तेहरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव, जलडमरूमध्य पर अपना रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपना हवाई अभियान जारी रख सकते हैं, लेकिन वर्षों से जारी उनके अधिकतम दबाव और 40 दिनों की बमबारी से ईरान की वार्ता की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अगर वे होर्मुज को लेकर युद्ध की ओर लौटते हैं तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर रुख (जो अभी तक अनसुलझा है) और भी कठोर हो जाएगा। अब ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि वह परमाणु अप्रसार संधि से भी बाहर आ सकता है। हालात ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उत्तर कोरिया भी 1985 में एनपीटी का सदस्य था। फिर भी उसने परमाणु परीक्षण किए और परमाणु बम भी बना लिए।

ओवैसी को चारा डाल रही है बीजेपी

असदुद्दीन ओवैसी के लिए यह नितांत निराला अनुभव था, सियासत कभी-कभी नए पेंचोखम में उलझा देती है। एक तरह से जब इस बात की तस्दीक हो गई कि संसद का इस बार का मानसून सत्र महज तीन हफ्तों का होगा और यह 20 जुलाई से प्रारंभ होकर 13 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। तब जनाब ओवैसी हैदराबाद में अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे तो उनके मोबाइल पर यकबयक घंटी बजी और ओवैसी यह देख कर हैरान रह गए कि फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि स्वयं लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला थे। जनाब के हैरत का कोई ठिकाना नहीं था कि दूसरी ओर से आवाज गूंजी- 'इस वक्त कहां हैं आप, आपके साथ बैठ कर एक चाय पीने की इच्छा हो रही थी।' ओवैसी ने जवाब दिया-'जनाब अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हूं, आप हुक्म करें, कल ही दिल्ली हाजिर हो जाऊंगा।' फिर दोनों नेताओं में बातचीत का सिलसिला चल पड़ा, सूत्रों की मानें तो दरअसल स्पीकर साहब को यह जानने में दिलचस्पी थी कि 'अयोध्या के चढ़ावा चोरी' के मुद्दे पर देश का मुसलमान क्या सोच रहा है।' कहते हैं इस पर ओवैसी ने जवाब दिया-'मुसलमान कोई अलग ग्रह का प्राणी नहीं है जनाब, वह भी वैसे ही सोचता है जैसा देश का कोई आम नागरिक या उसका हमवतन हिंदू सोचता है कि जो जगह खुदा की इबादत को बनी है वहां यह सब नहीं होना चाहिए था।

' कहते हैं स्पीकर साहब ने ओवैसी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि संसद में आपके बोलने का मैं भी कायल रहा हूं, वैसे भी आप एक बैरिस्टर रहे हैं, सो, बेहद नपा-तुला बोलते हैं, यह अलग बात है कि आपका रुझान एक धर्म विशेष के साथ है, फिर भी पूरा देश आपको सुनना चाहता है, सो मैं चाहता हूं कि इस बार आप सदन में विस्तार से बोलें, पूरा देश आपको सुनेगा। इस पर ओवैसी ने कहा-जनाब हमारे तो कुल दो ही सांसद हैं, हमें समय तो बहुत कम अलॉट होगा। स्पीकर ने कहा-इस बात की चिंता आप मुझ पर छोड़िए, दिल्ली आकर मिलिए, साथ चाय पीते हैं, गपशप लड़ाते हैं। अब इस मुलाकात के पीछे एक गूढ़ वजह है, दरअसल भाजपा अयोध्या के चढ़ावा चोरी मामले से खासी आहत है, अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। सो, केंद्र नीत भाजपा सरकार धार्मिक स्थलों के चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए एक नया कानून लाना चाहती है, जिसके तहत चाहे वह किसी भी धर्म की पूजा स्थली हो इसका संपूर्ण ऑडिट सरकार की निगरानी में होगा, ताकि एक-एक पैसे का हिसाब-किताब मिलाया जा सके। महाराष्ट्र के उत्साही मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने इस आशय का बिगुल भी फूंक दिया है, नासिक में 300 करोड़ का एक जमीन घोटाला सामने आया है जो एक क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ा मामला है और यह जमीन चर्च की बताई जाती है जिसे अवैध रूप से बेच दी गई है। अब फड़णवीस सरकार ऐसे मामलों की जांच के लिए कमेटियां बनाने को तत्पर है, फिर बकायदा इनके लेन-देन का ऑडिट भी किया जाएगा। यूपी जहां आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव आहूत है, इसको लेकर कांग्रेस में असहमतियों के स्वर उभरने लगे हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर यह एक मान्य अवधारणा है कि यहां के तमाम बड़े राजनैतिक फैसले कांग्रेस का एक कद्दावर नेता खुद लेता है।

पर जब इस दफे यूपी में कांग्रेस प्रभारी बनाने की बारी आई तो ऐसी ही एक राय को दरकिनार रखते एक विवादास्पद चेहरे राजेंद्र पाल गौतम के हाथों यूपी की कमान सौंप दी गई। जबकि एक बड़े नेता की राय एक पुराने समर्पित कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी के पक्ष में थी। तर्क था कि यूपी का ब्राह्मण इस वक्त भाजपा से खासा नाराज है, सो तिवारी के रूप में एक ब्राह्मण चेहरे को आगे करने से, ब्राह्मण समाज व अगड़े वोटरों की सहानुभूति कांग्रेस के साथ बढ़ेगी। प्रमोद तिवारी के अखिलेश यादव से बेहद निजी व प्रगाढ़ रिश्ते हैं, जो सपा से गठबंधन की स्थिति में फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इसके अलावा प्रमोद तिवारी पार्टी के लिए चुनावी फंड जुटाने में भी सक्षम हैं। वहीं एक अन्य बड़े नेता को हर वक्त घेरे रखने वाली मंडली ने उनके दिमाग में यह बात डाल दी है कि 'कांग्रेस को दलित वोटरों पर पूरा दांव लगाना चाहिए, दलित इस वक्त उहापोह की स्थिति में है, मायावती से बहुत हद तक उनका मोह भंग हो चुका है और वे किसी नए आशियाने की तलाश में भटक रहे हैं।' इसी मंडली ने बड़े नेता के समक्ष तर्क पेश किए कि 2014 के चुनाव में मायावती को 19.77 फीसदी दलितों के वोट मिले थे, जो 22 के विधानसभा चुनाव में घट कर 13 फीसदी रह गया और 2024 के लोकसभा चुनावों में तो दलितों ने (मायावती के सजातीय वोटरों को छोड़ कर) एक तरह से बहिन जी का साथ छोड़ ही दिया था, उनकी पार्टी बसपा को 24 के चुनावों में मात्र 9 फीसदी वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस नेता के करीबी इसे एक मौके की तरह देखते हैं सो, उन्होंने चुपके से घाट-घाट का पानी पी आए दलित नेता राजेंद्र पाल का नाम आगे कर दिया, बड़े नेता की गलती यह रही कि उन्होंने इस नेता से पूछे बगैर इसे 'हां' भी कर दिया। अब इस नेता ने भी यूपी के मामलों में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया है। जब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने घरेलू परिचित और भाजपा युवा मोर्चा के नेता अभिषेक कुमार बंटी को बांकीपुर की अपनी सीट से मैदान में उतारा था, तब से बांकीपुर के गली-गली में यह नारा शोर मचा रहा था-'अभिषेक बंटी, बांधेंगे गले में घंटी' चूंकि दूसरी ओर मैदान में प्रशांत किशोर थे, जो अपनी राजनैतिक अस्मिता तलाशने की लड़ाई में उतरे हुए हैं, सो जाने-अनजाने यह सीट बेहद 'हॉट सीट' में शुमार हो गई है। यूं अचानक अभिषेक बंटी की जाने यह कौन सी घंटी बजी कि उन्होंने ऐन वक्त चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया, अपने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को एक चिट्ठी लिख दी। सो, भगवा पार्टी में भी तूफान आ गया, चूंकि उस वैन नबीन भी पटना में ही थे, सो आनन-फानन में नीरज कुमार सिन्हा के रूप में एक नया उम्मीदवार ढूंढा गया, ये भी भाजयुमो से ही सियासी सफर तय कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अब लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि सबकी घंटी बजाने का इरादा रखने वाले बंटी को आखिर हुआ क्या तो प्रशांत किशोर कैंप की ओर से दबे-छुपे इस बात का दावा हुआ कि अभिषेक बंटी के परिवार से जुड़े लोगों के चारा घोटाले में संलिप्तता और उसके दस्तावेज पीके के हाथ लग गए हैं। पर इस बारे में कोई भी कुछ खुल कर कहने को राजी नहीं, सो बात अब बंटी व पीके के दरम्यान की रह गई है। पिछले दिनों भाजपा के एक बड़े नेता ने कम से कम पांच न्यूज चैनलों के संपादकों को अपने घर चाय पर आमंत्रित किया। इनमें से एक एडिटर की पैठ तो भाजपा में इस कदर है कि बड़े-बड़े भगवा नेताओं के भी वे कान काट लें। संपादकों संग चाय पर सर्वशक्तिमान ने अलग-अलग राजनैतिक मुद्दों पर बेहद विस्तार से चर्चा की। फिर बात चंदा चोरी या चंदा चंपत मामले पर आकर ठहर गई। दरअसल, यह भाजपानिष्ठ संपादक जी का कहना था कि 'इस मुद्दे को आखिरकार चैनल वाले बार-बार क्यों दिखा रहे हैं, क्यों इस बात को इतना तूल दे रहे हैं जबकि एसआईटी इस पर अपना काम कर रही है निष्पक्ष भाव से।' फिर उन्होंने अपने न्यूज चैनल का हवाला देते हुए कहा कि उनके चैनल ने गरिमा का ध्यान रखते हुए इस मामले की रिपोर्टिंग की है, बाकी चैनलों को भी इसी परिपाटी का अनुसरण करना चाहिए। पर संपादक जी तब दंग रह गए जब बड़े नेता ने छूटते ही कह दिया कि 'इस पूरे मामले से हमारी पार्टी का क्या लेना-देना, हम इसमें अपनी नाहक नाक भी नहीं घुसेड़ना चाहते, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जिन लोगों ने चोरी की है उन्हें उचित सजा भी मिलनी चाहिए तभी एक सही उदाहरण सामने रखा जा सकेगा। रही बात न्यूज रिपोर्टिंग की तो चैनलों को भी अपना काम उतनी ही मुस्तैदी से करना चाहिए।' बड़े नेता का जवाब सुन कर भाजपा भजनी संपादक महोदय के होश ही फाख्ता हो गए। यह कहानी बिहार के एक सीनियर नेताजी की है, जिनकी भगवा रवानी का हर कोई कायल है। कभी ये बिहार सरकार में मंत्री थे, अब भाजपा सांसद हैं। सो, ये नेताजी जब भी ट्रेन के फर्स्ट क्लास कूपे में सफर करते थे इनके साथ हमसफर एक महिला होती थीं, जानने वाले सब यही जानते थे कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि नेताजी की धर्मपत्नी हैं, सो सफर में उन्हें सम्मान भी बराबर का ही मिलता रहा है। एक दिन इत्तफाक से नेताजी के साथ इनकी मुंहबोली नहीं अपितु असली वाली धर्मपत्नी सफर कर रही थीं, सफर पटना से दिल्ली का था। पटना से ट्रेन ने अभी कुछ ही दूरी तय की थी कि नेताजी को टॉयलेट जाना पड़ गया, इसी बीच टिकट चैकर आ धमका, उन्होंने कूपे के दरवाजे पर नॉक किया, अंदर प्रवेश किया तो देखा नेताजी के कूपे में एक अलग महिला है, सो उसने छूटते ही पूछ लिया- 'आप कौन' नेताजी की पत्नी ने बताया 'मैं उनकी मिसेज' इस पर टीटीई महोदय ठठाकर हंस पड़े, बोले-हमको बुड़बक समझती हैं। हम भाभी जी को पहचानते नहीं हैं, जो हमेशा साथ चलती हैं। फिर क्या था जब नेताजी टॉयलेट से लौट कर कूपे में आए तो फिर जो हंगामा बरपा कि उन्हें भाग कर फिर से अपने को टॉयलेट में ही बंद कर लेना पड़ा।

हाय राम : लूट या चोरी

जब भारत सरकार के एक पूर्व सचिव ने यह बताया कि उन्होंने और उनके परिवार ने अयोध्या स्थित राम मंदिर को स्वर्ण-मंडित रामचरितमानस भेंट की है, तो यह खबर व्यापक चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इससे भी अधिक चिंता तब हुई, जब यह सामने आया कि इस ग्रंथ का मूल्य लगभग पांच करोड़ रुपये था। प्रारंभ में इसे मंदिर परिसर में प्रदर्शित किया गया, किंतु बाद में वहां से हटाकर किसी अन्य स्थान पर रख दिया गया। वर्ष 2023 में एस. लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी सरस्वती ने 151 किलोग्राम वजनी रामचरितमानस, जिसे तांबे पर स्वर्णाक्षरों में अंकित किया गया था, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित किया था। इस ग्रंथ के निर्माण के लिए दंपति ने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी, यहां तक कि परिवार की कुछ संपत्तियां बेचकर प्राप्त राशि भी खर्च कर दी। इसके निर्माण पर लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत आई थी। इस अलंकृत ग्रंथ में कुल 10,902 चौपाइयां और श्लोक तांबे के पृष्ठों पर अंकित हैं। इन पृष्ठों पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है तथा अक्षरों को भी स्वर्ण से अलंकृत किया गया है। यह ग्रंथ अप्रैल 2024 में मंदिर को समर्पित किया गया। प्रारंभिक दिनों में इसे प्रतिदिन भगवान रामलला की प्रतिमा के समक्ष पूजा-अर्चना के लिए रखा गया था, जिसकी तस्वीरें भी लक्ष्मी नारायण को भेजी गई थीं। हालांकि, कुछ समय बाद यह ग्रंथ सार्वजनिक रूप से दिखाई देना बंद हो गया। मंदिर के कई चक्कर लगाने और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मिलने के लिए कई दिनों तक इंतजार करने के बाद जब लक्ष्मी नारायण की उनसे मुलाकात हुई, तो उन्हें बताया गया कि मंदिर को प्राप्त सभी भेंटों को प्रदर्शित करना संभव नहीं है। लक्ष्मी नारायण का आरोप है कि अंतिम बातचीत के दौरान चंपत राय ने उनसे कहा-मैं जो चाहूंगा, वही करूंगा। मुझे बार-बार परेशान मत कीजिए। आज लक्ष्मी नारायण स्वयं को आहत और निराश महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी श्रद्धापूर्वक की गई यह भेंट लूट ली गई है। अपने परिवार के भगवान राम और राम मंदिर आंदोलन से गहरे जुड़ाव को याद करते हुए लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उनके परिवार के पास सदियों पुरानी रामायणकालीन एक प्रति है। उनका कहना है कि जब लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन के दौरान पहली बार राम मंदिर के लिए ईंट संग्रह अभियान शुरू हुआ था, तब पहली ईंट उनकी पत्नी के निर्देशन स्थित मायके से भेजी गई थी, जिसे बाद में कन्याकुमारी ले जाया गया। लक्ष्मी नारायण ने यह भी बताया कि उनके द्वारा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भेंट की गई इसी प्रकार की श्रीमद्भागवत का वहां प्रतिदिन विधिवत पूजन होता है। इसके लिए उन्हें समुचित दस्तावेज और आधिकारिक रसीद भी उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि, लक्ष्मी नारायण अकेले ऐसे दानदाता नहीं हैं। यह कोई एकाकी घटना भी नहीं है। दान की राशि या मूल्य चाहे जितना भी रहा हो, ऐसे कई अन्य लोग हैं जो इसी प्रकार के अनुभव साझा कर रहे हैं। राम मंदिर को दान में दी गई चांदी की ईंटों और सिल्लियों के गायब होने के भी कई आरोप सामने आए हैं। उदाहरण के तौर पर, चार किलोग्राम वजनी चांदी की एक ईंट के लापता होने का मामला भी चर्चा में है। इसके अलावा यह आरोप भी लगाए गए हैं कि मंदिर को दान में मिले स्वर्ण आभूषण चोरी कर उन्हें पिघलाकर सोने के बिस्कुटों (गोल्ड बिस्किट) में बदल दिया गया। ऐसा किए जाने की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि इससे मूल दान की पहचान समाप्त हो जाती है। इन सभी आरोपों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले पर आलोक कुमार ने एक राष्ट्रीय दैनिक से कहा, 'हम आहत हैं, हमें शर्म है और हमें खेद है।' चूंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संचालन की जिम्मेदारी चंपत राय के पास है, जो स्वयं विश्व हिन्दू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, इसलिए इस पूरे मामले में विश्व हिन्दू परिषद का रुख अपेक्षाकृत नरम माना जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि विश्व हिन्दू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं और वर्तमान में जांच के दायरे में हैं। आलोचकों का कहना है कि नैतिक आधार पर चंपत राय से स्वयं को अलग करने, उनके विरुद्ध संगठनात्मक कार्रवाई करने या सार्वजनिक रूप से जवाबदेही तय करने के बजाय विश्व हिन्दू परिषद उनकी भूमिका को महज 'लापरवाही' तक सीमित बताकर मामले की गंभीरता को कम करके पेश कर रही है। आलोक कुमार ने इस पूरे घटनाक्रम को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए मामले की गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया है। हालांकि, अब तक विश्व हिन्दू परिषद की ओर से 'हम आहत हैं' कहने के अलावा कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है। संगठन ने न तो चंपत राय से सार्वजनिक दूरी बनाई है और न ही उन्हें परिषद से हटाने की दिशा में कोई कार्रवाई की है। हालांकि आलोक कुमार के हवाले से यह कहा गया है कि 'किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी' लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस पहल दिखाई नहीं देती। फिलहाल ये बातें महज खोखले आश्वासन प्रतीत होती हैं।

कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन इससे पहले यह भी अपेक्षित है कि चाहे विश्व हिन्दू परिषद हो या स्वयं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जांच के दायरे में आए लोगों के विरुद्ध संगठनात्मक स्तर पर भी सख्त कार्रवाई करें। शुरुआत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा से होनी चाहिए। यद्यपि मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा गठित किसी भी जांच एजेंसी की अपनी विश्वसनीयता संबंधी चुनौतियां होती हैं। उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है और उस पर सत्ता के इशारे पर काम करने के आरोप भी लग सकते हैं। विशेष रूप से इस मामले में स्थिति दोधारी तलवार जैसी है और जांच की निष्पक्षता तथा वस्तुनिष्ठता को लेकर पर्याप्त आशंकाएं मौजूद हैं। एक ओर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से इस बात से असंतुष्ट बताए जाते रहे हैं कि राम मंदिर के संचालन और प्रबंधन में राज्य सरकार की कोई भूमिका या अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य-दोनों सरकारों को अत्यंत सावधानी से कदम उठाने होंगे, क्योंकि मंदिर में दान की कथित लूट का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव गंभीर हो सकता है। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर जवाबदेही किस स्तर तक तय की जाती है और किन-किन लोगों पर इसकी आंच पहुंचती है। फिलहाल कार्रवाई की जद में अपेक्षाकृत छोटे स्तर के लोग दिखाई दे रहे हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि प्रभावशाली और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का क्या होगा क्या केवल इसलिए पर्याप्त होंगे यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा या अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी कथित अनियमितताओं में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे या नहीं। किंतु यदि वे इन घटनाओं से अनभिज्ञ रहे अथवा जानबूझकर आंखें मूंदे रहे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सवा पॉकेटफला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे।

वृक्षारोपण महायज्ञ- पडरौना नगर पालिका ने लगाए सैकड़ों पौधे, पर्यावरण संरक्षण का दिलाया संकल्प

पडरौना, कुशीनगर।

उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 अभियान के तहत नगर पालिका परिषद पडरौना ने रविवार को मानस कॉलोनी स्थित श्री बुढ़िया माता मंदिर परिसर एवं जलकल भवन परिसर में व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के निर्देशन तथा अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के छायादार एवं पर्यावरण हितैषी पौधों के रोपण से हुई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, पालिका कर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संदेश दिया। अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण की सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व का भी आधार हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भविष्य के लिए प्रत्येक नागरिक को पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी नियमित देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित वृक्षारोपण महायज्ञ अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं हरित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद पडरौना शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जन-जागरूकता कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने लगाए गए पौधों की सुरक्षा एवं संरक्षण का संकल्प लिया और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी संतराम सरोज, श्री बुढ़िया माता मंदिर के महंत वीरेंद्र नाथ जी महाराज, सभासद श्याम साहा, संतोष मद्धेशिया, रामाश्रय गौतम, बलवंत सिंह, एबादुल्लाह, मैनुद्दीन, करीम, क्यामुद्दीन, छोटे, मृत्युंजय दीक्षित, बिपिन जायसवाल, सत्री मिश्रा, अशोक अग्रवाल, आकाश पाण्डेय, सचिन शाहा, आकाश वर्मा, अनिल कुमार, मदन चौधरी, धर्मेंद्र मद्धेशिया, अनिल पाण्डेय, धर्मेंद्र जायसवाल, भोला साहा, केदार मद्धेशिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

गौ-तस्करी गिरोह के चार सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

कप्तानगंज, कुशीनगर।

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कप्तानगंज पुलिस ने गौ-तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के चार सदस्यों के खिलाफ सोमवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार गिरोह के सरगना प्रेम कुमार तिवारी निवासी नवादा परसौनी, थाना उचकागांव (गोपालगंज, बिहार) सहित जिब्रिल शाह निवासी शिवपुर बुजुर्ग, थाना कसया (कुशीनगर), रामजनम सिंह निवासी उचकागांव (गोपालगंज, बिहार) तथा बुद्धू शेख उर्फ भुद्दू शेख निवासी नवादा परसौना, थाना उचकागांव (गोपालगंज, बिहार) के विरुद्ध धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह उत्तर प्रदेश से बिहार एवं अन्य स्थानों पर गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी कर आर्थिक लाभ अर्जित करता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 17 सितंबर 2023 को कप्तानगंज पुलिस ने पिकअप वाहन संख्या ब्रक्र 06त्न-9491 से गोवंशीय पशुओं को वध के लिए ले जाते समय चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान दो पिकअप वाहनों से चार जीवित एवं एक मृत गोवंशीय पशु बरामद किए गए थे। इस मामले में थाना कप्तानगंज पर मुकदमा संख्या 428/2023 के तहत गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में पहले से मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि आरोपित संगठित गिरोह बनाकर गौ-तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर रहे थे। इसी आधार पर उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

डिजिटल लर्निंग अभियान में प्रदेश के शीर्ष स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य, भाजपा जिला कार्यालय में समीक्षा बैठक संपन्न

रविंद्र नगर धूस, कुशीनगर।

भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय, रविंद्र नगर धूस में सोमवार को जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय की अध्यक्षता में विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा एवं वर्तमान अभियानों को गति देने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि प्रदेश संगठन द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले कार्यक्रमों एवं अभियानों में कुशीनगर सदैव अग्रणी रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति-नीति, इतिहास तथा केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सरल ऐप के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण के जरिए दी जा

रही है। प्रशिक्षण के बाद प्रश्नोत्तरी पूरी करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम में कुशीनगर वर्तमान में प्रदेश में आठवें स्थान पर है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से जनपद जल्द ही प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा। बैठक में डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने पर पटहेरवा मंडल अध्यक्ष अमलेश तिवारी एवं कुबेरस्थान मंडल अध्यक्ष बचा सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा के शैलेन्द्र तिवारी को भी 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए सम्मानित किया गया। जिले के आईटी संयोजक नमो नारायण मौर्य ने पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। अभियान के जिला संयोजक प्रवीण गुंजन एवं सह संयोजक विश्व रंजन आनंद कार्यक्रम के संचालन में सहयोग कर रहे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष लल्लन मिश्रा ने कहा कि प्रशिक्षित एवं जागरूक कार्यकर्ता ही संगठन को मजबूत बनाते हैं और आगामी चुनावों में पार्टी की विजय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बैठक में खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय, पडरौना विधायक मनीष जायसवाल, फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, हाटा विधायक मोहन वर्मा, रामकोला विधायक विनय गोंड, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदंबा सिंह, प्रेमचंद्र मिश्रा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राधेश्याम गोंड, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल सहित जिला पदाधिकारी, मोर्चा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ऊमस भरी गर्मी में रूला रही बिजली, लो वोल्टेज के साथ कटौती से बढ़ी दुश्वारियां

महराजगंज।

शहर में बिजली की आंख मिचौली से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। ऊमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को पूरी रात नींद नहीं आई। क्योंकी बिजली गुल रही। हल्की बारिश के बाद रविवार रात में ऊमस बढ़ गई। इस बीच बैकुंठपुर पावर हाउस में तकनिकी खराबी होने के कारण देर रात बिजली आई, लेकिन एक से दो घंटे के अंदर ही चली गई। इससे लोग परेशान रहे। दिन भी वोल्टेज ठीक नहीं रहने से लोगों को परेशानी हुई, लेकिन समस्या के समाधान की दिशा में जिम्मेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई। रविवार को मौसम खराब रहने से इसका असर हर क्षेत्र पर पड़ा। सबसे अधिक परेशान बिजली नहीं रहने से हुई। दिन भी रूक रूक कर बिजली कटती रही। इस बीच तमाम घरों में बिजली के उपकरण भी खराब हो गई। रविवार शाम को

महराजगंज शहर में कई मोहल्लों में लो वोल्टेज से लोग परेशान, बिजली नहीं रहने से रात में नींद नहीं हुई पूरी

बिजली गुल हुई तो करीब नौ बजे के बाद आई। वोल्टेज ठीक नहीं रहने से लोगों को इसका फायदा नहीं मिला। गांधी नगर, इंदिरा नगर, विस्मिल नगर, चिऊरहा समेत अन्य मोहल्ले में लोग परेशान रहे। देर रात बिजली आने के बाद भी कुछ देर में कट गई। गांधी नगर राकेश कुमार ने बताया कि बिजली नहीं रहने से रात में नींद पूरी नहीं हुई। इसका असर सेहत पर भी दिखा। सोमवार सुबह सिर में दर्द होने लगा। जिला अस्पताल जाकर दवा लेनी पड़ी। गीता देवी ने बताया की सोमवार सुबह बच्चों को स्कूल में देरी हो गई। टंकी में पानी नहीं भर पाया था। ऐसे में परेशानी हुई। बरसात में इस तरह की समस्या अक्सर हो जाती है। दिन भर बिजली आने जाने का क्रम जारी रहा, लेकिन वोल्टेज ठीक नहीं रहा। पंखा रेक रहा था। चलने पर भी हवा नहीं लग रही थी। ऊमस से बचों समेत बुजुर्गो को परेशानी हुई। शहर में करीब 60 हजार की आबादी को समस्या झेलनी पड़ी लेकिन जिम्मेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई। उधर, बिजली निगम के मुताबिक लोड बढ़ने से बिजली ट्रीप हो जा रही है। यादातर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है। अधीक्षण अभियंता वाईपी सिंह ने बताया कि समस्या का समाधान करा दिया गया है। ओवरलोड की समस्या से निपटने के लिए शहर में अभियान चलाकर जांच पड़ता की जाएगी। जर्जर तारों को बदलने के साथ ही ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ाई जा चुकी है।

गंडक प्रदूषण की शिकायत पर हरकत में नगर पंचायत, डीएम को भेजी निस्तारण रिपोर्ट

भटनी देवरिया।

छोटी गंडक नदी में नालियों का गंदा पानी गिरने की शिकायत पर नगर पंचायत भटनी बाजार ने कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी को निस्तारण रिपोर्ट भेज दी है। वार्ड नंबर-10 ठाकुर जी कुटी निवासी सुमेश वर्मा ने ऑनलाइन शिकायत कर गंदे पानी के प्रवाह को रोकने तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना की मांग की थी।

नगर पंचायत के अनुसार शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनकी मौजूदगी में

नाली की सफाई कराई, एसटीपी निर्माण के लिए जिला स्तर पर कार्रवाई जारी

संबंधित नाली की सफाई कराई गई तथा नदी में कचरा जाने से रोकने के लिए लगाई गई स्क्रीन जाली का निरीक्षण किया गया। आख्या में बताया गया है कि नगर क्षेत्र में एसटीपी की स्थापना के लिए जिला प्रशासन को पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम इस संबंध में कार्रवाई कर रही है। नगर पंचायत का दावा है कि की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता संतुष्ट हैं और उन्होंने लिखित रूप से संतुष्टि पत्र भी उपलब्ध कराया है। वहीं स्थानीय लोगों को अब एसटीपी निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने और छोटी गंडक नदी को प्रदूषण से राहत मिलने का इंतजार है।

जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल के 16वें दिन 8.2 किलो घटा वजन, गिरा शुगर लेवल

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को कहा कि शिक्षाविद् और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का वजन जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से 8.2 किलोग्राम कम हो गया है। पार्टी ने यह भी बताया कि उनका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल गिरकर 67 mg/dl. हो गया है और वेद सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर जवाब देने की अपील की। वांगचुक के अनशन का 16वां दिन होने पर बीजेपी ने कहा कि उनकी सेहत और बिगड़ गई है। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर पार्टी का विरोध प्रदर्शन सोमवार को 24वें दिन में प्रवेश कर गया, जबकि विपक्षी नेताओं और छात्र समूहों का समर्थन प्रदर्शन स्थल पर जारी रहा। सीजेपी की ओर से जारी हेल्थ अपडेट के मुताबिक, वांगचुक का ब्लड प्रेशर 107/70 mg/dl. रिकॉर्ड किया गया। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सरकार से अपील की कि वे इस मामले को अहंकार की लड़ाई न बनने दें। दिपके ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वांगचुक की भूख हड़ताल का 16वां दिन है। मैं सरकार से गुज़ारिश करता हूं कि इसे अहंकार की लड़ाई न बनाएं क्योंकि यहाँ इंसानी ज़िंदगी दांव पर लगी है। उन्होंने आगे कहा, अपनी गलती मानना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, यह समझदारी, जवाबदेही और अपनी गलती सुधारने की इच्छा की निशानी है। हम बस जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। सीजेपी के अनुसार, उस दिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने विरोध स्थल का दौरा किया और आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त की। CPI(M) सांसद अमरा राम ने भी आंध्र प्रदेश और राजस्थान के वरिष्ठ CPI(M) नेताओं के साथ स्थल का दौरा किया और मांगों का समर्थन किया। दौरा करने वाले नेताओं ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक प्रस्तावित शांतिपूर्ण मार्च का भी समर्थन किया। सीजेपी के अनुसार, आप के प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन के लिए अपना समर्थन दोहराया, एक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की मांग की, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया। CPI(M) लिबरेशन से जुड़े ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य - नेहा, मनीष, दीपक और आर्यन - ने विरोध स्थल पर एक अलग मंच पर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी। पॉलिटिकलमंटर्स एक बयान में AISA ने कहा कि आतिशी ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से मुलाकात की और लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई, क्योंकि छात्र हफ्तों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे और सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। संगठन ने यह भी कहा कि भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की सेहत और बिगड़ गई है, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

ड्रोन से दहल उठे खाड़ी देश, तेहरान का दावा- अमेरिकी सैन्य ठिकाने किए तबाह

ईरान ने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। यह कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में जैसे को तैसा बताई गई। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की दखलअंदाजी रोकने की चेतावनी दी।

तेहरान। पश्चिम एशिया में पिछले चार महीनों से जारी संघर्ष अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ दिनों पहले तक जिस शांति वार्ता से उम्मीद की किरण दिख रही थी, वह अमेरिका और ईरान के बीच शर्तें न मानने के आरोपों की भेंट चढ़ गई। ऐसे में शांति की कोशिशें थमते ही दोनों देशों के बीच भीषण हमलों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। इसी बीच, ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सोमवार को एक सनसनीखेज दावा करके वैश्विक राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। आईआरजीसी का कहना है कि उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से तीन चरणों में बड़ा हमला किया है। ईरान ने इस सैन्य कार्रवाई को जैसे को तैसा नाम दिया है। हालांकि, ईरान के इन दावों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।

ईरान ने कहां-कहां हमले का दावा किया?

ईरानी मीडिया के अनुसार, यह हमला पिछले 48 घंटों से अमेरिकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद किया गया। आईआरजीसी ने हमले को तीन चरणों में बांटकर अंजाम देने का दावा किया है।

तीन चरण में कहां-कहां हमले किए गए

पहला चरण में ईरान के द्वारा जॉर्डन को निशाना बनाया गया। दावा है कि ईरान ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे वहां मौजूद ईंधन डिपो और गोला-बारूद के गोदामों में आग लग गई। दूसरे चरण के तहत ईरान ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया।

ईरान के मुताबिक, वहां अमेरिकी हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर, पी-8 विमान के हैंगर और ड्रोन कमांड सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं तीसरा चरण के तहत ईरानी सेना ने कुवैत के अली अल-सालेम एयरबेस पर हमला कर अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और ईंधन टैंकों को तबाह करने का दावा किया गया है। साथ ही अहमद अल-जाबेर एयरबेस पर लगे एक खास रणनीतिक रडार को भी नष्ट करने की बात कही गई है।

15-18 वर्ष है प्रयोग की उम्र- पोस्को पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

झूठी शान के लिए केस दर्ज न कराएं माता-पिता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किशोरों के आपसी संबंधों में पॉक्सो कानून के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि जब 16 से 18 साल के बच्चे आपस में रिश्ता बनाकर चले जाते हैं, तो माता-पिता अपने तथाकथित सम्मान की रक्षा के लिए उन पर आपराधिक केस दर्ज करा देते हैं। शीर्ष अदालत ने साफ-साफ कहा कि राय किसी लड़के और लड़की के भागने को भला कैसे रोक सकता है? पॉक्सो कानून बच्चों के यौन उत्पीड़न और शोषण को रोकने के लिए बना है। 15 से 18 साल की उम्र बहुत संवेदनशील होती है। यह जीवन में

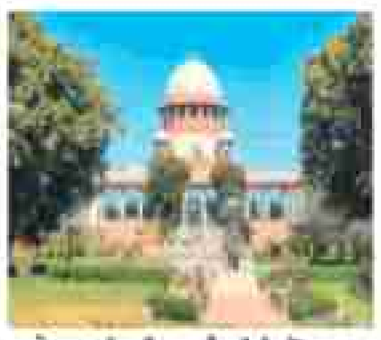

प्रयोग करने की उम्र है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन मामलों को वास्तव में पॉक्सो का केस माना जाना चाहिए? अदालत ने चिंता जताई कि ऐसे मामलों में आखिर में हमें युवाओं को बरी ही करना पड़ता है। यह पूरा मामला किशोरों की निजता के अधिकार से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। दरअसल, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में किशोर लड़कियों को दो मिनट के आनंद के लिए रिश्तों में न फंसने और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित टिप्पणी को पूरी तरह खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने शीर्ष अदालत को बताया कि जिस घटना से यह विवाद शुरू हुआ था, वह अब पूरी तरह सुलझ चुका है। वह मामला एक नाबालिग लड़की के 25 साल के व्यक्ति के साथ भागने का था। सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बातचीत के बाद रिपोर्ट दी गई थी कि इस तरह के पॉक्सो मामलों में हमारी मौजूदा व्यवस्था कैसे विफल हो रही है।

चंदा चोरी- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को भेजा नोटिस, एसआईटी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 जुलाई) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान की कथित चोरी की निष्पक्ष और तय समय-सीमा के भीतर जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने उत्तर प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दान की कथित चोरी के मामले में अपनी जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र और राज्य की ओर से पेश हुए, ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में दाखिल की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, जब कोर्ट याचिकाओं पर विचार करेगा और एसआईटी की जांच के नतीजों की समीक्षा करेगा।

मनमोहन सिंह के लिए निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की आत्मा था,मोदी के लिए राजनीतिक साधन - कांग्रेस

नई दिल्ली ।

कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के अतीत के एक कथन का हवाला देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि वह निर्वाचन आयोग (ईसी) को लोकतंत्र की आत्मा मानते थे, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आयोग को राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के एक साधन के रूप में देखते हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) एस वाई कुरैशी से डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा कही गई यह बात मीडिया की सुर्खियों में आ गई है, जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग को हमारे लोकतंत्र की आत्मा बताया था। कुरैशी ने अपनी पुस्तक में मनमोहन सिंह के साथ अपनी बातचीत का उल्लेख किया है। रमेश ने दावा किया कि सिंह की यह सोच मौजूदा प्रधानमंत्री के निर्वाचन आयोग को लेकर नजरिये से बिल्कुल अलग थी। रमेश ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह ने कभी यह कल्पना नहीं की होगी कि निर्वाचन आयोग उनके उत्तराधिकारी के प्रभाव में इस तरह आ जाएगा और ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जो इतने खुलेआम और निर्लज्जता से पक्षपात करेंगे कि वे प्रधानमंत्री के राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से भी वंचित कर देंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संस्थाओं का राजनीतिकरण करना न तो मनमोहन सिंह के स्वभाव में था और न ही उनकी विचारधारा का हिस्सा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इतिहास डॉ. मनमोहन सिंह के लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके नेतृत्व के लिए उनके प्रति सदैव उदार रहेगा।

केंद्र सरकार को परवाह नहीं- उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक के अनशन को दिया समर्थन, राहुल गांधी से की अपील

मुंबई। शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को एक बड़ा एलान किया है। उन्होंने दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया है। यह आंदोलन नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहा है। उद्धव ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के प्रदर्शन का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने झंडे अलग रखकर इस आंदोलन का साथ देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी इस प्रदर्शन का समर्थन करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने वांगचुक से भूख हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया। सोमवार को वांगचुक के अनशन का 16वां दिन था। उद्धव ने कहा कि वांगचुक की जान बहुत कीमती है। लेकिन केंद्र सरकार असंवेदनशील है। सरकार को इस आंदोलन की कोई परवाह नहीं है। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर यह आंदोलन पिछले 24

दिनों से जारी है। शिक्षक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी 28 जून को इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वह तभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सीजेपी की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। इसके साथ ही मई में नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले। मेडिकल प्रवेश परीक्षा पिछले महीने दोबारा आयोजित की गई थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी दल अपने राज्यों में इस मुद्दे पर प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जब सीजेपी संसद मार्च करेगी, तब शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में प्रदर्शन करेगी। शिवसेना यूबीटी के सांसद मानसून सत्र में संसद के अंदर भी यह मुद्दा उठाएंगे। उद्धव ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी तरफ, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि वांगचुक जिंदा रहें। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि देश को लद्दाख के इस कार्यकर्ता की प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन उन्हें देशद्रोही कहा गया और जेल में डाल दिया गया। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर पिछले साल सितंबर में लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत उनकी हिरासत रद्द किए जाने के बाद उन्हें 14 मार्च 2026 को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था। उद्धव ने यह भी बताया कि वह 18 जुलाई को नागपुर जाएंगे। वहां वह राम रक्षा आंदोलन में भाग लेंगे। यह आंदोलन अयोध्या के राम मंदिर में मिले दान में कथित हेराफेरी के खिलाफ शुरू किया गया है।

7 दिन में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून

नई दिल्ली । राजस्थान, गुजरात और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बीते 3-4 दिनों में कमजोर पड़ा मानसून 20 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा। सैटेलाइट इमेज में पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर घने बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6-7 दिनों तक कई जगह अच्छी से भारी बारिश होने का अनुमान है।

अंकित शर्मा हत्याकांड : पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, कोर्ट में फूट-फूटकर रोया; बोला- मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ

नई दिल्ली । 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को हत्या, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश का दोषी पाया है। जैसे ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने फैसला सुनाया, ताहिर हुसैन अदालत में ही फफक-फफककर रोने लगा। सजा के ऐलान के बाद मीडिया के कैमरों के सामने उसने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। यह मामला 25 फरवरी 2020

का है, जब आईबी में तैनात अंकित शर्मा कार्यालय से घर लौटने के बाद लापता हो गए थे। अंकित के पिता रवींद्र कुमार की शिकायत के अनुसार, स्थानीय लोगों ने जानकारी दी थी कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है और शव को चांद बाग पुलिया के पास एक मस्जिद के पास नाले में फेंक दिया गया है। बाद में अंकित का शव खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था। पिता ने आरोप लगाया था कि ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने अंकित की हत्या की और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को ठिकाने लगा दिया। अदालत ने ताहिर हुसैन को न केवल हत्या, बल्कि वैमनस्य फैलाने, दंगा करने, मारपीट और आपराधिक बल प्रयोग के आरोपों में भी दोषी पाया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दंगाई ताहिर हुसैन के दफ्तर में जमा हुए थे। ताहिर के साथ 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मामले दर्ज थे, जिनमें से अदालत ने पांच को दोषी करार दिया है। दोषियों की सूची में हसीन उर्फ मुल्लाजी, नाज़िम, कासिम और समीर खान जैसे नाम शामिल हैं। यह घटना फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा थी। इन दंगों में कुल 53 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। दंगों में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया था। अदालत ने माना कि ताहिर हुसैन ने सार्वजनिक अशांति फैलाने के लिए लोगों को उकसाने वाले बयान दिए थे।

वियतनाम नाव हादसा

15 भारतीयों के पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचे, अंतिम संस्कार के लिए गृह राज्यों को भेजे गए

नेशनल डेस्क । वियतनाम में पिछले सप्ताह हुए दर्दनाक नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर सोमवार रात भारत लाए गए। वियतनाम एयरलाइंस की एक विशेष उड़ान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, हो ची मिन्ह सिटी से उड़ान VN 979 रात करीब 9:19 बजे मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर पीड़ितों के परिजन और सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद पार्थिव शरीरों को अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह राज्यों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। मृतकों में 10 तमिलनाडु, तीन आंध्र प्रदेश और दो केरल के रहने वाले थे। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। पार्थिव शरीरों को कोयंबटूर, चेन्नई, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम भेजा जा रहा है, जहां परिजन अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। यह हादसा शुक्रवार को वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास हुआ था। भारतीय पर्यटकों का एक समूह स्पीडबोट से घूमकर लौट रहा था, तभी नाव पलट गई। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और चार वियतनामी चालक दल के सदस्य सवार थे। हादसा होन मे रट नगोई द्वीप से करीब 400 मीटर की दूरी पर हुआ। इस दुर्घटना में 16 भारतीय पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया। इलाज के बाद वे भारत लौट चुके हैं।

अब शिक्षा में क्रांति का समय- राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब बेईमान वसूली का तंत्र बन गई है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का समय आ गया है। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों से अपने दूसरे संवाद से पहले यह बात कही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि दोनों ने जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा, भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमानी- ये चार शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा

व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सच यही है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है।उन्होंने आगे कहा, जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज, तनाव और निराशा में धकेल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफिया को जन्म दिया, जो तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत एक झटके में लूट लेता है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, यहां दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों को ठेके और तरक्की मिलती है। लेकिन सजा किसे मिलती है? उन छात्रों को, जिन्हें टूटे सपनों के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री यह सब देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने चुप्पी चुनी है। जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया है। और मीडिया में? बस एक लंबा सन्नाटा है। अब बहुत हुआ। अब शिक्षा में क्रांति का वक्त है। राहुल गांधी ने छात्रों से अपील की कि वे 17 जुलाई को देहरादून में उनसे जुड़ें और छात्रों की गूंज अभियान को और मजबूत बनाएं।

यूपी में 33 जिला मुख्यालयों के बीच बनेंगे नए नेशनल हाईवे

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा सड़कों से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी परियोजनाओं को गति देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस समीक्षा में राजधानी लखनऊ को उन सभी जिलों से फोर लेन मार्ग से जोड़ने पर गहन मंथन हुआ जो अभी तक लखनऊ से फोर लेन से नहीं जुड़े हैं। 33 जिला मुख्यालयों के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन में विकसित करने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार, दो लेन अथवा दो लेन से कम क्षमता वाले मार्गों को चौड़ा करने पर भी मंथन किया गया। सोमवार को मॉल-एवेन्यू मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख इंजन बनकर उभरा है, इसलिए यहां विश्वस्तरीय सड़क संपर्क विकसित करना केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, उपयोगिताओं के स्थानांतरण तथा अन्य विभागीय औपचारिकताओं को समयबद्ध निस्तारित करते हुए परियोजनाओं को गति दिए जाने के निर्देश दिए। बोली बाईपास के काम में वृक्षों की कटान पर उन्होंने कहा कि वृक्षों को काटने के बजाय आधुनिक तकनीक से उन्हें कहीं और लगाया जाए। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में ब्लैक स्पॉट के वैज्ञानिक सुधार, आधुनिक संकेतक व्यवस्था तथा सड़क सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया

जाना चाहिए। सड़क निर्माण के साथ दुर्घटनाओं में कमी लाने के उपायों पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कई सड़क परियोजनाएं केवल सड़क संपर्क को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। प्रत्येक क्षेत्र को उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

सक्षम भारत की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्केन करे।